Impact Factor (SJIF): 6.126 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 26/August/2025 **IJRAW:** 2025; 4(10):458-461 **Accepted:** 08/October/2025

विकसित भारत एवं भूगोल पाठ्यक्रम

*[1]आकांक्षा चतुर्वेदी

*[1]शोधार्थी, भूगोल विभाग, जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

देश में भाषा और साम्प्रदायिकता के हावी होने के कारण इस कठिन समय में भूगोल का उचित पाठ्यक्रम हमारी बहुत कुछ सहायता कर सकता है। देश की महानता तथा गौरव बताकर इस देश के निवासियों में देश–प्रेम की लहर दौड़ाकर भूगोल भावात्मक एकता स्थापित कर सकता है। हम सभी उस सुन्दर तथा विशाल देश के वासी हैं जहाँ गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी आदि नदियाँ हैं। यह देशवासियों की हैं। गगनचुम्बी हिमालय सभी देशवासियों का है। भूगोल प्रदेशों की संकुचित सीमाओं से उठाकर हममें उन्नत, विशाल दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। देश के अन्दर हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई के प्रश्न को भूगोल नहीं उठने देता है। देश की एकता पर राष्ट्रीयता को भावना जाग्रत करता है। चम्बल नदी मध्य प्रदेश या राजस्थान की ही नहीं है, वरन् सम्पूर्ण देश की है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, नर्मदा, भाखड़ा या दामोदर बांधों के बारे में कहा जा सकता है। बड़े उद्योगों के बारे में भी कहा जा सकता है। भूगोल के पाठ्यक्रम में ऐसे अनेक स्थल आते हैं, जहाँ संकुचित दृष्टिकोंण से ऊपर उठकर एक विशाल तथा उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोंण पोषित किया जा सकता है। वही दृष्टिकोंण राष्ट्रीय और सामाजिक एकता में योगदान देता है। लगातार शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों ने भूगोल पाठ्यक्रम में कई आधारभूत बदलाव किये हैं। जैसे नवीन तकनीकी का प्रयोग, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, वैश्विक समझ विकसित करने वाली विषय वस्तु का समावेश के साथ–साथ वैश्विक भागीदारी के लिये तैयार करने के प्रयासों को को प्राथमिकता मिली है।

मुख्य शब्दः वैश्वीकरण, भारतीय शिक्षा, भूगोल पाठ्यक्रम।

प्रस्तावना

विकसित भारत में शिक्षा

शिक्षा की किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भूमिका असंदिग्ध है। क्योंकि विकास की वर्तमान और भावी संभावनायें मानव संसाधन के विकास पर निर्भर है तथा मानव संसाधन का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। विकसित देशों ने इसीलिये शिक्षा पर प्राथमिकता से ध्यान दिया। भारत में भी आजादी से पहले और बाद में विभिन्न आयोग और समितियों ने शिक्षा पर विचारणीय कार्य किया है। आजादी से पहले की बात करें तो मैकाले का विवरण पत्र, वुड घोषणा पत्र, भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोग आयोग, वुड एबट समिति, सार्जेंट प्रतिवेदन आदि समितियों ने शिक्षा पर महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा में गतिशीलता बनाये रखने के लिये अनेक आयोग और समितियों का गठन किया गया। यथा समय शिक्षा नीतियाँ तथा योजनायें बनाई गई। ताराचन्द समिति, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, आचार्य नरेन्द्र देव समिति, श्रीमाली समिति, कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति, जनार्दन रेड्डी समिति, यशपाल समिति आदि का गठन किया गया। साथ ही विभिन्न आयोगों के सुझाव पर पूरे भारत में शिक्षा नीतियाँ लागू की गई। लेकिन देखा जाये तो 1991 के बाद भारत तथा विश्व के अन्य भागों में साम्यवादी व्यवस्था के समाप्त होने के बाद से ही बदलाव की शुरुआत होने लगी थी। इसी वजह से समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन आना शुरु हो गया। इन परिस्थितियों ने समाज को बदलना और प्रभावित करना शुरु कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में शिक्षा भी प्रभावित हुई, तथा इस का परिदृश्य

***Corresponding Author:** आकांक्षा चतुर्वेदी

बदलने लगा। वास्तव में वैश्वीकरण आर्थिक घटनाओं से जुड़ी ऐसी प्रक्रिया है, जो भौगोलिक दूरियों को कम करने, आपसी अन्तः क्रिया बढ़ाने तथा संपर्क की व्यवस्थाओं से संबंधित है। साथ ही यह विभिन्न समुदायों, राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक जाल है जो वैश्विक संपर्क बनाता है। दुनियाभर में सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, चाहे वे सांस्कृतिक हो या आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय हो। जाहिर है कि यह एकरूपता के पक्ष में और स्थानिकता के विरुद्ध है। आर्थिक पक्ष की जिस प्रधानता का यहाँ जिक्र किया गया है, वह शिक्षा को गहरे से प्रभावित कर रही है, जिससे ज्ञान प्राप्त करने, बच्चे के संपूर्ण विकास, सीखने, स्थानिकता जैसी धारणाएं हतोत्साहित होती है और शिक्षार्थियों के उपभोक्ता जैसी भूमिका में आने का खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि नब्बे के दशक में जो आर्थिक नीतियाँ लागू की गई उनसे सरकार ने अपने आप को कई जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, तथा सरकार द्वारा संचालित होने वाले कई क्षेत्रों को बाजार के हवाले कर दिया। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की बाढ़ आ गई। यह बाढ़ सिर्फ़ शहरों तक ही सीमित नहीं रही, गांवों और कस्बों तक भी पहुंच गई। यानी शिक्षा का लक्ष्य मात्र तात्कालिक जरुरतें पूरी करने मात्र का साधन मान लिया गया है, जो किसी खास क्षेत्र में वेतनभोगी बना सकने योग्य बना सके। शिक्षा में रचनात्मकता, आलोचनात्मकता और संवाद क्षमता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को नजरअंदाज किया जाने लगा है। अतः यह कहा जाना कि भले ही हमने राजनीतिक आजादी प्राप्त कर ली हो, पर ज्ञान पर आज भी पश्चिमी सभ्यता का ही प्रभाव है। यही वजह रही है कि आज साहित्य, समाज, दर्शन, भाषा आदि की शिक्षा को बोझ माना जाने लगा है।

इन्ही चुनौतियों के मद्देनज़र शिक्षाविद अनिल सद्गोपाल ने 'शिक्षा में बदलाव का सवाल' में लिखा है "वह पाठ्यक्रम कैसा होगा जो हमें विश्व की विभिन्न धाराओं का सामना करने तथा उनसे कुछ सीख पाने के लिये इस प्रकार से सशक्त करे कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें? अभी तक हमने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बुनियादी सिद्धान्तों पर सवाल उठाने की जुर्रत भी नहीं की है जो बुरी तरह विफ़ल हो चुकी है।" (सदगोपाल, 2009)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 में लिखा गया है कि "शिक्षा का उद्देश्य लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार तथा दूसरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करना होना चाहिये।" (एन.सी.ई.आर.टी, 2005) साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 यह अनुसंशा करती है कि विद्यार्थी को बाहरी जीवन व स्थानीय पर्यावरण से जोड़ा जाये।

भारत विश्व में अपनी राष्ट्रीय आय में से शिक्षा पर खर्च करने वाले देशों की सूची में से काफ़ी पीछे है, जबकि हमारी सरकार अपनी कुल राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद पर खर्च करती है। यह एक जरुरी सवाल है कि शिक्षा पर खर्च होने वाला कोटा लगातार कम होता जा रहा है। इस का प्रभाव यह हुआ कि सरकारी संस्थाएँ बिखर गई, "जब हम शिक्षितों की बात करेंगे तो फ़िर हमें उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बांटना होगा, शोध में बांटना होगा। प्राथमिक शिक्षा एक तरफ़ सरकारी संस्थानों से प्राइवेट संस्थानों की तरफ़ लगातार रुख करती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ़ लगातार महंगी होती चली जा रही है। एक जमाना था जब केवल सरकारी स्कूल हुआ करते थे, ट्रस्ट स्कूल हुआ करते थे और बहुत थोड़े निजी शिक्षण संस्थाओं तक चुनिंदा अमीरों के बच्चे पहुंच पाते थे। आज गरीब, किसान, मजदूर भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं का स्तर लगातार गिरा है।" (मीणा, 2019)

भारत में शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता और सरकारी संसाधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने निजीकरण का समर्थन किया और कहा कि देश में शिक्षा के अवसरों का दायरा बढाने की आवश्यकता है तथा उसमें निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना उचित है। "एक सवाल शिक्षा की उपादेयता का भी है। वर्तमान में बाजार और पूंजी के प्रभाव में शिक्षा डिग्री मात्र रह गई है। शिक्षित लोगों को न रोजगार उपलब्ध है और न समाज के विकास में कोई भूमिका। शिक्षा सामाजिक विकास का माध्यम तभी हो सकती है जब उसका सीखने से संबंध हो और पाठ्यक्रम समाजोन्मुखी हो। इसलिये शिक्षा की सामाजिक उपादेयता सुनिश्चित करनी होगी और हमें देश के विकास में शिक्षा को सहयोगी रूप में आगे लाना होगा।" (मीणा, 2019)

शिक्षा में सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग से शिक्षा की परंपरागत प्रणाली को बहुत बदल के दिया। दूरस्थ शिक्षा का संप्रत्यय भी संभव हो पाया। इसके साथ–साथ शिक्षा की विषयवस्तु दृष्टिकोंण और अध्यापन की आवश्यकतायें भी बदली है। यही कारण है कि आज मानविकी विषयों से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन आया। परंपरागत शिक्षण विधियों की जगह नवीन आधुनिक विधियों ने ले ली, स्व–अधिगम को प्रोत्साहित किया गया। ग्रुप डिस्कशन, सेमीनार, कोपरेटिव लर्निंग, वर्कशोप, ट्युटोरियल, ब्रेन स्टार्मिंग आदि का प्रयोग शिक्षा में किया जाने लगा।

विकसित भारत और भूगोल पाठ्यक्रम

भूगोल सामाजिक विज्ञान का विषय है और समाज का नजदीक से अध्ययन करता है। अतः नयी आर्थिक नीतियों के प्रभाव स्वरूप बदलते समाज के मद्देनजर यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पाठ्यचर्या के स्वरूप के बारे में लिखा है कि "अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता को सुदृढ करने के लिये पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिये कि वह युवा पीढी को इस के लिये सक्षम बना सके कि वह

नई प्राथमिकताओं व बदलते सामाजिक संदर्भ मे उभरते दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में अतित का पुनर्मूल्यांकन कर पाएं।" (एनसीईआरटी, 2005) साथ ही एन.सी.एफ़. 2005 पाठ्यचर्या के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं मान कर इन्हें सीखने के लिये सामग्री के रूप में प्रस्तावित करता है।

एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महसूस करते हुए एन.सी.एफ़. 2005 यह मानता है कि "हम पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि हम सारे बच्चों को जाति, धर्म संबंधी अन्तर, लिंग और असमर्थता संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी स्कूली माहौल मुहैया करायें जो उनको शिक्षा ग्रहण में मदद पहुँचाएँ तथा सशक्त बनाएँ।" (एनसीईआरटी, 2005) साथ ही एन.सी.एफ़. 2005 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य 'शिक्षा बिना बोझ के' भी है, जिसे प्राप्त करने के लिये पाठ्यचर्या निर्माण के "पाँच निर्देशक सिद्धान्तों का प्रस्ताव रखा है–

- ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।
- पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना।
- पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन करना कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया कराये बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बन कर रह जाये।
- परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
- एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिंतायें समाहित हो।" (एनसीईआरटी, 2005)

भूगोल उन विषयों में से एक है जो एन.सी.एफ़. 2005 के उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य और पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धों और इन सब के विकास के माध्यम से इस विषय में समाज का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि आज भूगोल मात्र प्राकृतिक वातावरण या आर्थिक उपादानों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका क्षेत्र अनेक गूढ़ विषयों जैसे–धर्म, औषध विज्ञान, जातियता, कला आदि को भी अपने में समाये हुए हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ है–भौतिक भूगोल और मानव भूगोल लेकिन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाये तो भूगोल की "समाजशास्त्र से समाज भूगोल, प्रजाति विज्ञान से प्रजातीय भूगोल, अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल, राजनीति विज्ञान से राजनीतिक भूगोल आदि भूगोल की प्रमुख भूगोल की उपशाखाएँ है जो व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई है।" (शर्मा, 2018)

आम तौर पर भूगोल का अर्थ मात्र उच्चावच, नदियाँ, जलवायु और मिट्टी के अध्ययन से लिया जाता है, जो संकीर्णता का द्योतक है। वास्तविकता तो यह है कि भूगोल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी के भौतिक वातावरण के साथ–साथ मानवीय क्रियाकलापों एवं उनके आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण आदि भी इसके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है।

भूगोल पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित का अध्ययन करवाया जाता है, जिसके तहत कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक 'भारत के लोग और अर्थव्यवस्था' में जनसंख्या, प्रवास, मानव विकास, मानव बस्तियाँ, भूसंसाधन, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि को स्थान दिया गया है। इसी कक्षा की 'मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त' पाठ्यपुस्तक में मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विश्व जनसंख्या, जनसंख्या संगठन,मानव विकास, परिवहन, संचार एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विषयवस्तु को महत्व दिया गया है। साथ ही प्रयोगात्मक कार्यों में आंकड़ें, आंकड़ों का संकलन, निरूपण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया है। कक्षा 11 में पाठ्यपुस्तक 'भारत भौतिक पर्यावरण' में भारत की स्थिति, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संकट, तथा आपदा प्रबंधन को संकलित किया गया है। 'भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त' में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, आन्तरिक संरचना, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, खनिज एवं शैल, भू–आकृतिक प्रक्रियाएँ, भू–आकृतियाँ तथा उनका विकास, वायुमण्डल का संघठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान, वायुमंण्डलीय परिसंचरण, मौसम प्रणालियाँ, वायुमण्डल में जल, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, महासागरीय जल तथा जल संचलन, पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित विषयवस्तु सम्मिलित थी। प्रायोगिक कार्यों में मानचित्र का परिचय, मापनी, अक्षांश, देशांतर और समय, प्रक्षेप, स्थलाकृतिक मानचित्र, वायुफ़ोटो का परिचय, मौसम यंत्र तथा चार्ट की जानकारी है।

भूगोल की पाठ्यवस्तु का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्यक्षीकरण सामग्री का उपयोग अधिक हो दूसरी आवश्यक बात यह है कि छात्रों की कल्पना शक्ति को जाग्रत करना चाहिए कि विभिन्न भौगोलिक वातावरणों में मानव स्वयं को किस प्रकार अपने जीवन को मोड लेता है। भूगोल की समस्त पाठ्य–सामग्री को सापेक्षिक कठिनाई के अनुसार के क्रम में रखना चाहिए। प्रादेशिक, मानव–क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक वातावरण इन तीन क्रमों के अनुसार ही पाठ्य–वस्तु का चयन होना चाहिए जिसके लिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–

- बच्चों के पूर्व ज्ञान को हम कहाँ तक जाग्रत कर सकते हैं।
- बच्चों के मूर्त रूप में कहाँ तक तथ्यों या विचारों को प्रदान कर सकते हैं।

प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण मे निम्नांकित सिद्धान्त ध्यान मे रखने चाहिए

1. भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण में भूगोल शिक्षण के

उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए जब भूगोल शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो पाठ्यक्रम निर्माण हो सकता है और वर्तमान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी संभव है

2. व्यापक पाठ्यकम् द्वारा 5 वर्षों में माध्यमिक स्कूल का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा में जिन क्षेत्रों का अधिक महत्व है, उनको अधिक विस्तृत रूप में पढ़ाना चाहिए। बच्चे अपने गृह–प्रदेश के विषय में भली–भांती जानकारी रख सके और दूसरे देशों के विषय में जो इससे सम्बन्ध रखते है, जानकारी, प्राप्त कर सकें। एक–दूसरे पर क्या प्रभाव पडता इसका अध्ययन भी छात्र भली प्रकार कर सकें।
3. सापेक्षिक कठिनाई के अनुसार पाठ्यक्रम की क्रमबद्धता।
4. भूगोल के विभिन्न भाग, जैसे– प्राकृतिक गणित, भूगोल, भूगोल, आर्थिक भूगोल का आपस में सम्बन्ध/रुचि का केन्द्र एक प्रदेश ही होना चाहिए। इस प्रदेश के प्राकृतिक जलवायु आर्थिक पहलुओं को समझना चाहिए।
5. भूगोल को स्कूल के दूसरे विषयों के सम्बन्ध के विषय में भी ध्यान रखना चाहिए।
6. गृह–प्रदेश तथा संसार प्रदेश में सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।
7. पाठ्यक्रम में क्रियात्मक कार्य के लिए बच्चों को अवसर देना चाहिए
8. पाठ्यक्रम में छात्रों को दुहराने के लिए अवसर होना चाहिए।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर पाश्चात्य भूगोलवेत्ताओं ने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में निम्नांकित पाठ्यक्रम रखने का सुझाव दिया हैं–

प्राथमिक स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम

इस स्तर पर छात्रों को भौगोलिक ज्ञान से परिचित कराना है, और ग्यारह वर्ष की अवस्था
पर छात्रों को अधिक ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता के लिए छोड़ देना हैं। प्राइमरी स्तर पर यह आशा करना कि छात्र क्रमबद्ध रूप से कार्य कर सकें, अधिक उचित नहीं होगा उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नांकित पाठ्यक्रम उचित होगा–

1. स्थानीय पड़ोस में प्रारंभिक निरीक्षण, ऋतुओं और सूर्य का निरीक्षण भी इसमें सम्मिलित हैं।
2. घर, स्कूल और पड़ोस के नक्शे बनाना और स्थानीय छ इंच शीट का प्रयोग।
3. मातृदेश के कुछ चुने हुए व्यक्तियों और उनके जीवन विषय के बारे में बतलाना।
4. दूसरे देशों की ओर दृष्टिपात–इनमें चित्रांकित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।
5. भौगोलिक खोजों का इतिहास।
6. वह देश जो हमारा जहाँ जल, भोजन पैदा करते हैं।
7. दूसरे देश के बच्चों का जीवन।

माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम

माध्यमिक कक्षायों में बालकों को भूगोल का शिक्षण संकेन्द्रीय विधि से देना चाहिए। इसमें संसार का आरम्भिक सर्वे, संसार का प्राकृतिक भूगोल की दृष्टि से अध्ययन, संसार का जलवायु तथा वनस्पति, संसार का आर्थिक, भूगोल, भोजन, बाजार तथा आवागमन के साधन, संसार का जलवायु तथा वनस्पति, कच्चा माल, अन्तिम रूप में से संसार का सर्वेक्षण जिसमें, पहले पांच वर्ष का किया हुआ कार्य सुसंगठित हो सकें और विशेष रूप से भारत की संसार में स्थिति को शमिल किया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम कुछ चुने हुये प्रसंगो से सम्बन्ध रखता है। पाठ्यक्रम की वास्तविक योजना स्थानीय जनपद से सम्बन्धित विषय उद्योग, सामाजिक और ऐतिहासिक विषय, मनुष्य की आवश्यकताओं से सम्बन्धित विषय–भोजन, जल, वस्त्र तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल, यातायात के साधन आदि प्रसंगानुसार होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सदगोपाल, (2009). शिक्षा में बदलाव का सवाल, नई दिल्ली, ग्रंथ शिल्पी।
2. एनसीईआरटी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद।
3. मीणा, (2019, जुलाई 19). ताकि विकास में सहयोगी बने शिक्षा लेख। उदयपुर, राजस्थान, भारत, राजस्थान पत्रिका।
4. शर्मा, के. (2018, नवंबर 13). मानव भूगोलः प्रकृति व विषय क्षेत्र. Retrieved जुलाई 24, 2019,
5. Agrawal, J.C. (1990). Curriculum reforms in India. New Delhi, Pp 42.
6. Bhatt, B.D. and Sharma, S.R. (1992). Principles of Curriculum pp 76.
7. Construction. New Delhi: Kanishka Publishing House, pp 77.
8. Dewal, O.S. (2004). National Curriculum. In Encyclopedia of Indian Education. New Delhi: NCERT, Pp 88A.